ए-45011/03/2024-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

नई दिल्ली दिनांक 05 अप्रैल, 2024

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को फरवरी, 2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को परिचालित करने का निदेश हुआ है।

सु. सामंत

(सुश्रुत सामंत)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 2309- 5244

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।

9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।

10. एमओएस (एफ) के पीएस, वित्त सचिव के पीपीएस, सचिव (ईए) के पीपीएस, सचिव (राजस्व) के पीपीएस, सचिव (व्यय) के पीपीएस, सचिव (दीपम) के पीपीएस।

11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, डीईए।

12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

13. श्री मनोज सहाय, एएस एवं एफए (वित्त)।

14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एवं सी)

15. सुश्री मनीषा सिन्हा, एएस (ओएमआई/क्रिप्टो संपत्ति और फंड बैंक)

16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागों के प्रमुख।

जेएस (आईपीपी/जेएस (आईएसडी) /जेएस (अन्वे) /जेएस (बजट) जेएस (एफएम) /सभी सलाहकार/सीएएए

17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

18. गार्ड फ़ाइल – 2024.

ए-45011/03/2024-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषय: फरवरी, 2024 के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।

1. माह के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियाँ:

वृहद आर्थिक सिंहावलोकन:

राष्ट्रीय लेखा के दूसरे अग्रिम अनुमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह जनवरी, 2024 में जारी पहले अग्रिम अनुमान में एनएसओ द्वारा अनुमानित 7.3 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक है। तीसरी तिमाही (तीसरी तिमाही; 8.4 प्रतिशत पर) में मजबूत वृद्धि ने वित्त वर्ष 24 में पूरे साल की वास्तविक जीडीपी वृद्धि में बढ़ोतरी की है। दिसंबर 2023 तिमाही के जीडीपी डेटा जारी होने के बाद, कई पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने जीडीपी विकास अनुमानों को संशोधित किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 8 प्रतिशत कर दिया, जबकि उसका पिछला अनुमान 7 प्रतिशत था। इसी तरह, बार्कलेज ने अपना अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया।

नीति आयोग का अनुमान है कि अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के अनुसार, गरीबी घटकर पांच प्रतिशत हो गई है, जो दर्शाता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं। एचसीईएस इस बात पर प्रकाश डालता है कि मासिक प्रति व्यक्ति घरेलू उपभोग व्यय (एमपीसीई) 2011-12 की तुलना में 2022-23 में दोगुना से अधिक हो गया है। 2022-23 में औसत अनुमानित एमपीसीई ग्रामीण भारत में ₹3,773 और शहरी भारत में ₹6,459 है। गरीबी में इस गिरावट का श्रेय पिरामिड के निचले पायदान पर मौजूद लोगों पर लक्षित सरकारी कार्यक्रमों को जाता है।

जनवरी, 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर तीन महीने के निचले स्तर 5.1 प्रतिशत पर आ गई। जनवरी, 2024 में मुद्रास्फीति में गिरावट खाद्य और मुख्य (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) दोनों घटकों के कारण है। मुख्य मुद्रास्फीति में लगातार आठवें महीने गिरावट जारी रही, जो मई, 2023 में 5.2 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी, 2024 में 3.5 प्रतिशत हो गई। पिछले दो महीनों की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट आई है, लेकिन अभी

भी इसमें और कमी आना बाकी है। जनवरी, 2024 में अधिकांश खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2024 के पहले 10 महीनों में मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ, खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4 प्रतिशत हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2023 की समान अवधि में यह 6.8 प्रतिशत थी।

अप्रैल 2023-जनवरी 2024 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान (आरई) का 63.6 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान आरई के 67.8 प्रतिशत से कम है। यह सुधार वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में कर संग्रह में बजट से अधिक वृद्धि और खर्च की गुणवत्ता में सुधार के कारण है। आपूर्ति पक्ष की अस्थिरता के बीच कर राजस्व में बढ़ोतरी से सरकार को उच्च व्यय को समायोजित करने में मदद मिली है। कुल मिलाकर, सकल कर राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 14.6 प्रतिशत की दर से बढ़ा। अप्रैल, 23 से जनवरी, 24 की अवधि में पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 26.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 29 प्रतिशत थी। राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय का अनुपात वित्त वर्ष 2011 में 6 से गिरकर वित्त वर्ष 24 में 3.7 हो गया (अप्रैल, 23 - जनवरी, 24)।

वित्त वर्ष 24 के पहले दस महीनों के दौरान, भारत के व्यापारिक निर्यात और आयात में क्रमशः 4.9 प्रतिशत और 6.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे व्यापारिक घाटे में कमी आई। माल व्यापार घाटा अप्रैल'22-जनवरी'23 तक 229.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर अप्रैल'23-जनवरी'24 में 207.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। प्रमुख वस्तुगत समूहों में वर्गीकरण से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों को छोड़कर सभी श्रेणियों में निर्यात में व्यापक गिरावट आई है। वित्त वर्ष 24 के पहले दस महीनों के दौरान शुद्ध सेवा व्यापार में 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तदनुसार, भारत का समग्र व्यापार घाटा (माल और सेवाएँ संयुक्त) वित्त वर्ष 2023 के पहले दस महीनों के दौरान 112 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वित्त वर्ष 24 की इसी अवधि में 70.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने मोबाइल फोन के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

वित्त वर्ष 2024 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को वैश्विक एफडीआई रुझानों के साथ-साथ प्रत्यावर्तन द्वारा निर्देशित किया गया है। आरबीआई के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर, 2023 के दौरान प्रत्यावर्तन में 41.5 प्रतिशत की तेज वृद्धि के कारण भारत में प्रत्यक्ष निवेश में 41.2 प्रतिशत की कमी आई ।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम :

(i) माननीया वित्त मंत्री ने 21 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में **वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की 28वीं** बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, एफएसडीसी के

सदस्य, सचिव (ईए), मुख्य आर्थिक सलाहकार और वरिष्ठ सलाहकार/सचिव (एफएसडीसी) भी उपस्थित थे।

(ii) माननीया वित्त मंत्री ने 21 फरवरी, 2024 को विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक (संचालन) सुश्री अन्ना बजेर्डे और प्रबंध निदेशक और विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी सुश्री अंशुला कांत से मुलाकात की।

(iii) भारत–यूएई ने 13 फरवरी, 2024 को **द्विपक्षीय निवेश संधि** पर हस्ताक्षर किए।

(iv) **जी20 ब्राज़ील प्रेसीडेंसी के तहत निम्नलिखित वित्त ट्रैक** बैठकें फरवरी, 2024 के दौरान आयोजित की गईं:

क) ब्राज़ीलियाई प्रेसीडेंसी के तहत **जी20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप (SFWG) की पहली बैठक** वस्तुतः 05-06 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई।

ख) **पहली जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) की बैठक** 28 - 29 फरवरी, 2024 को साओ पाउलो, ब्राज़ील में आयोजित की गई । वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने किया और भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डिप्टी गवर्नर डॉ. माइकल पात्रा ने किया।

ग) एफएमसीबीजी की विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने के लिए एफएमसीबीजी की बैठक 26-27 फरवरी, 2024 को दूसरी जी20 वित्त और सेंट्रल बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक से पहले हुई ।

घ) जी20 एफएमसीबीजी बैठक के मौके पर, ब्रिक्स की रूसी अध्यक्षता में **पहली ब्रिक्स एफएमसीबीजी बैठक** 27 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई और ब्रिक्स वित्तीय सहयोग एजेंडा के तहत 2024 के लिए रूसी अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।

ङ) **एनडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स** ने 27 फरवरी, 2024 को जी20 एफएमसीबीजी बैठक के मौके पर साओ पाउलो में एक विशेष बैठक में भी मुलाकात की। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की विशेष बैठक रूस को ऋण वितरण को फिर से शुरू करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसे रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से रोक दिया गया।

(v) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की गईं/ में भाग लिया गया:

(क) रूस की अध्यक्षता में पहली **ब्रिक्स वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्टिज़ (एफसीबीडी) की बैठक** वर्चुअल रूप से 7 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई थी और रूसी अध्यक्ष के तहत वित्तीय सहयोग की प्राथमिकताओं और डिलिवरेबल्स पर चर्चा की गई थी।

(ख) **आईएफएडी गवर्निंग काउंसिल का** 47वां सत्र 14-15 फरवरी, 2024 को रोम, इटली में आयोजित किया गया था।

(ग) **पीपीपी मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी)** की 113वीं बैठक 16 फरवरी, 2024 को i) उत्तर प्रदेश में उत्तरी बाईपास (एनएएम) और दक्षिणी अयोध्या बाईपास (एसएबी); ii) असम में गुवाहाटी रिंग रोड के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोजित की गई थी।

(घ) **पीपीपीएसी** की 114वीं बैठक 21 फरवरी, 2024 को i) आगरा-ग्वालियर राजमार्ग; ii) रायपुर-धनबाद आर्थिक गलियारे के भाग के रूप में सीमा-गुमला-भरदा खंड; (iii) खड़गपुर से मोरेग्राम खंड तक 4 लेन पहुंच-नियंत्रित आर्थिक गलियारा के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए हुई थी।

(ङ) **भारत-उरुग्वे बीआईटी वार्ताएं** वर्चुअल रूप से दिनांक 20 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई थीं।

(च) **भारत-ताजिकिस्तान बीआईटी वार्ताएं** वर्चुअल रूप से दिनांक 28-29 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई थीं।

(छ) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 26 फरवरी, 2024 को जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय (बीएमजेड) के राज्य सचिव श्री जोचेन फ्लैसबार्थ से मुलाकात की, ताकि इस वर्ष भारत में आयोजित होने वाले नेताओं के स्तर के भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श के लिए परिकल्पित प्रारंभिक उपायों पर चर्चा की जा सके।

(ज) **पीपीपी संरचना टूलकिट – जल और स्वच्छता क्षेत्र** पर कार्यशाला दिनांक 26 - 27 फरवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी।

(झ) **बाह्य सहायता-प्राप्त परियोजनाओं पर स्क्रीनिंग कमेटी** की 146वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई थी।

(ञ) आईएमएफ के **प्रारंभिक चेतावनी समूह (ईडब्ल्यूजी)** की 40वीं बैठक वर्चुअल रूप से दिनांक 29 फरवरी, 2024 को आयोजित की गई थी, जिसमें प्रारंभिक चेतावनी सूचकांक में सुधार के तरीकों, वित्तीय अनुभाग से संबंधित विकास आदि पर चर्चा की गई थी।

(ट) **भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत ऋण व्यवस्था पर अंतर-मंत्रालयी स्थायी समिति** (आईएमएससी) की बैठक दिनांक 26 फरवरी, 2024 को पुनर्गठित एलओसी, उनकी प्रावधान संबंधी आवश्यकताओं, संवितरण को जारी रखने

और एलओसी से संबंधित अन्य मामलों के बारे में चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी।

(vi) द्विपक्षीय और बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के साथ निम्नलिखित **ऋण समझौतों** पर हस्ताक्षर किए गए:

क) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. जेपीवाई 26.133 बिलियन की राजस्थान जलवायु समुत्थानशीलता संवर्धन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवा सुधार परियोजना।

ii. 16.211 बिलियन जेपीवाई की उत्तराखंड शहरी जल आपूर्ति परियोजना।

iii. हरियाणा में 16.215 बिलियन डॉलर की बागवानी मूल्य श्रृंखला का निर्माण।

iv. 10.008 बिलियन जेपीवाई से नागालैंड मेडिकल कालेज अस्पताल की स्थापना।

v. 23.697 बिलियन जेपीवाई की तेलंगाना सामाजिक और ग्रासरूट इनोवेशन परियोजना।

vi. उत्तर-पूर्व सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना: जेपीवाई 15.561 बिलियन का चरण VII (मेघालय एनएच 127बी)।

vii. पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी सुधार परियोजना ': 34.537 बिलियन जापानी येन का चरण-3 (ट्रांच-II)।

viii. चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड का निर्माण: 49.847 बिलियन जेपीवाई से चरण 2।

ix. समर्पित फ्रेट कॉरिडोर परियोजना: 40.000 बिलियन जेपीवाई से चरण -1 (किश्त 5)।

ख) विश्व बैंक के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अर्थव्यवस्थाओं के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए एकीकृत सेवा प्रावधान और नवाचार।

ii. 386.31 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बिहार एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन परियोजना (बीआईडब्ल्यूआरएमपी)

ग) एशियाई विकास बैंक के साथ हस्ताक्षरित ऋण:

i. 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से असम में जलवायु समुत्थानशील ब्रह्मपुत्र एकीकृत बाढ़ और नदी तट कटाव जोखिम प्रबंधन परियोजना

(घ) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (एमआईजीए) ने डीएफसीसीआईएल के साथ 100 मिलियन अमेरिकी डालर से एमयूएफजी बैंक के साथ गारंटी की संविदा पर हस्ताक्षर किए।

(Vii) **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के कार्यकारी बोर्ड** में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई:

(क) कार्यपालक निदेशकों के नियमित चुनाव;

(ख) जलवायु वित्त पर आईएमएफ का कार्य;

(ग) लिक्टेंस्टीन की नई सदस्यता।

(Viii) माह के दौरान निम्नलिखित **अधिसूचनाएं जारी** की गई थी:

(क) भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में ₹ 100/- मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान स्वीकार किए गए एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा वाले एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या : 02

विभाग में स्वीकृति की प्रतीक्षा में : 11

6. फरवरी, 2024 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित वीजीएफ परियोजनाओं की संख्या: पांच परियोजनाएं

7. फरवरी, 2024 के दौरान स्वीकृत/अनुमोदित पीपीपीएसी परियोजनाओं की संख्या: शून्य

8. फरवरी, 2024 के दौरान भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएएस) के तहत अनुशंसित एलओसी: शून्य

9. फरवरी, **2024** के दौरान आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की संख्या: 06